1	2	3
3. *Ammonium Sulphate*		
100 Kg. packing	925	925
4. *Muriate of Potash*		
10 Kg. packing . .	795	—
5. Di-Ammonium phosphate . . .	2210	2210
6. *Ammonium Nitro Phosphate*		
20-20-0 . .	1590	1845 (FACT) 1760 (FCI)
24-24-0 .	2045	2080 (IFFCO) 2045 (MFL)
7. *NPK*		
15-15-15 .	1520	1520 (FCI)
17-17-17 . .	1810	1810 (MFL)

STOCKS OF FERTILIZERS AS ON 31-5-1977.

Nitrogen . .	8,66,184 tonnes
P_2O_5 . .	2,45,626 "
K_2O	38,991 "
Total	11,50,801 tonnes

नगरीय सम्पत्ति के अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में शिकायतें

4640. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा अधिनियम के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें मिली है ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और दिल्ली में कितने लोगों ने इस सम्बन्ध में अपनी तफ सील दाखिल की है, और

(ग) इस अधिनियम के अधीन सरकार ने दिल्ली में कितने प्लाट अपने तहत लिये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के विरुद्ध अब तक 291 अभ्यावेदन प्राप्त हुए ।

(ख) इन में से 147 अभ्यावेदन निम्न लिखित मामलों से संबंधित थे :—

(i) भवन-निर्माण योजनाओं का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है ।

(ii) इन अधिनियम की धारा 26 तथा 27 और हस्तान्तरण से संबंधित कागजातों के रंजीकरण को ध्यान में रखते हुए भूमि तथा सम्पत्ति के हस्तान्तरण के बारे में कठिनाइयां अनुभव की जा रही है ;

(iii) इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दिए गए विवरणों की जांच में विलम्ब के कारण अनुचित कष्ट हो रहा है ; और

(iv) इस अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य सरकारें शीघ्रातिशीघ्र छूट नहीं दे रही हैं ।

क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, इन अभ्यावेदनों की पावती सूचना भेज दी गई थी तथा इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को उनके उचित कारवाई के लिए भेज दिया गया था । जहां भी आवश्यक समझा गया, राज्य सरकारों को उचित मार्गनिर्देशन भेज दिए गए ।

144 अभ्यावेदनों में सुझाव दिया गया था कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को रद्द किया जाए अथवा सशक्त रूप से संशोधन किया जाए । इनकी पावती भेज दी है । जिन सुझावों पर इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जहां तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है, यह बतलाया गया है कि इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन 7811 विवरण प्रस्तुत किए गए हैं ।

(ग) जी बिल्कुल नहीं ।

Cases and Appeals about wakf Properties in Bhatinda District (Punjab)

4641. SHRI OM PARKASH TYAGI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) how many cases or appeals concerning Wakf properties are pending in the courts of District Bhatinda (Punjab) in which Central Government or Custodian of India is a party;

(b) what is the value of property involved in each such case or appeal, the names of the parties, brief synopsis of the dispute involved and since when each case or appeal is pending and

(c) what steps are being taken for their speedy disposal?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) According to the information furnished by the Punjab Wakf Board, no case or appeal concerning Wakf properties is pending in the Courts of District Bhatinda (Punjab) in which Central Government or Custodian of Evacuee Properties India is a party.

(b) and (c). Do not arise.

Shortage of Housing Accommodation for Central Government Employees in Goa, Daman and Diu

4642. SHRI AMRUT KASAR: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government Officers who are transferred to the Union territory of Goa, Daman and Diu from other States are facing acute shortage of housing accommodation in Goa;

(b) if so, what steps have been taken to remove this shortage of housing accommodation in Goa; and

(c) whether the Central Government officers are reluctant to stay in Goa due to this housing problem?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Central Government Employees Welfare Co-ordination Committee, Goa, had submitted a Memorandum explaining *inter alia* that in Goa, and particularly in the three major cities, *viz.*, Panaji, Margao and Vasco, there was acute dearth of residential accommodation witb the result that the employees of the Central Government who came on transfer to